रिलायंस को मिली एसीसी बैट्री बनाने की जिम्मेदारी

भारी उद्योग मंत्रालय ने गुणवत्ता और लागत के आधार पर पीएलआइ के तहत कंपनी का किया चयन

- एनर्जी को स्टोर करने की एडवांस तकनीक है एसीसी बैट्री, जरूरत पर इसे बिजली में बदल सकते
- इसका इस्तेमाल इलेक्ट्रिक वाहनों से लेकर पावर बैकअप जैसी जगहों पर किया जा सकेगा
- पहले चरण में तीन कंपनियों को 30 जीडब्ल्यूएच स्टोरेज विकसित करने का काम दिया गया

3620
करोड़ रुपये के इंसेंटिव दिए जाएंगे योजना के तहत

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : भारी उद्योग मंत्रालय ने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (पीएलआइ) स्कीम के तहत 10 गीगावाट-आवर (जीडब्ल्यूएच) क्षमता वाले एडवांस्ड केमेस्ट्री सेल (एसीसी) बैट्री मैन्यूक्चरिंग के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज का चयन किया है। मंत्रालय के मुताबिक गुणवत्ता और लागत मैकेनिज्म के आधार पर यह चयन किया गया है। एसीसी ऊर्जा को स्टोर करने की एडवांस तकनीक है। इसके तहत इलेक्ट्रिक एनर्जी को इलेक्ट्रोकेमिकल ऊर्जा के तौर पर स्टोर किया जाता है और फिर उसे जरूरत पड़ने पर बिजली में बदला जा सकता है।

इसका इस्तेमाल इलेक्ट्रिक वाहनों से लेकर पावर बैकअप जैसी जगहों पर किया जा सकता है। पीएलआइ स्कीम के तहत 10 जीडब्ल्यूएच एसीसी स्टोरेज क्षमता विकसित करने के लिए सरकार की तरफ से 3620 करोड़ रुपये के इंसेंटिव दिए जाएंगे। रिलायंस के अलावा एसीएमई क्लीनटेक साल्यूशन, अमार राजा एडवांस सेल टेक्नोलाजी, अन्वी पावर इंडस्ट्रीज, जेएसडब्ल्यू नियो एनर्जी, लुकास टीवीएस लिमिटेड ने पीएलआइ स्कीम के तहत एसीसी बैट्री स्टोरेज मैन्यूफैक्चरिंग के लिए आवेदन किए थे।

एसीसी मैन्यूफैक्चरिंग के पहले चरण के आवंटन का काम पूरा : पीएलआइ स्कीम के तहत वर्ष 2021 में 50 जीडब्ल्यूएच क्षमता वाली एसीसी मैन्यूफैक्चरिंग सुविधा विकसित करने का प्रस्ताव लाया गया था। दो साल पहले पीएलआइ स्कीम के तहत एसीसी मैन्यूफैक्चरिंग के पहले चरण के आवंटन का काम पूरा हो चुका है। पहले चरण में तीन कंपनियों को 30 जीडब्ल्यूएच एसीसी स्टोरेज विकसित करने का काम दिया गया है। एसीसी की 50 जीडब्ल्यूएच क्षमता विकसित करने के लिए सरकार ने 18,100 करोड़ रुपये का प्रविधान रखा है। एसीसी क्षमता विकसित होने से कम लागत पर बिजली का स्टोरेज किया जा सकेगा और पेट्रोल और डीजल की जगह बिजली का धड़ल्ले से इस्तेमाल हो सकेगा। इससे पेट्रोल और डीजल पर हमारी निर्भरता कम होगी।

एक-दो महीने में फेम-3 योजना को मंजूरी देगी सरकार : कुमारस्वामी

नई दिल्ली, प्रेट्र : केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने बुधवार को कहा कि सरकार अपनी प्रमुख इलेक्ट्रिक परिवहन अपनाने वाली योजना 'फेम' के तीसरे चरण को एक या दो महीने में अंतिम रूप दे देगी। उन्होंने कहा कि एक अंतर-मंत्रालयी समूह इस योजना के लिए प्राप्त सुझावों पर गौर कर रहा है। इसके साथ ही हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाने और मैन्यूफैक्चरिंग (फेम) से जुड़ी योजना के पहले दो चरणों में पेश हुई समस्याओं के समाधान के प्रयास भी जारी हैं। फेम-3 अस्थायी 'इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम' (ईएमपीएस) 2024 की जगह लेगी। इस योजना की अवधि सितंबर में समाप्त हो रही है। कुमारस्वामी ने कहा, 'फेम-3 पर कई सुझाव आ रहे हैं। फेम-1 और फेम-2 में जो भी खामियां थीं, उन्हें कैसे दूर किया जाए हम इस पर भी काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय ने भी कुछ सुझाव दिए हैं। इसके लिए हमारा अंतर-मंत्रालयी समूह काम कर रहा है।' फेम-3 को अंतिम रूप देने की समयसीमा के बारे में पूछे जाने पर मंत्री ने कहा, 'मुझे लगता है कि एक या दो महीने के भीतर इस पर काम पूरा हो जाएगा।' यह पूछे जाने पर कि क्या फेम-3 प्रस्ताव को एक या दो महीने में मंजूरी के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल के पास भेजा जाएगा मंत्री ने कहा, 'अब भी कई सुझाव आ रहे हैं। हमें उन सभी पर गौर करना होगा।'